



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2019/चैत्र 12, 1941

No. 111]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2019/CHAITRA 12, 1941

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019

विषय: राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (2019)

#### सं. 15 (5)/2015-आई.सी.डी (खंड 1) .—I. प्रस्तावना

I.1. देश का सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (आईटी-आईटीईएस) उद्योग भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह उद्योग सभी क्षेत्रों, अर्थात् कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विनिर्माण इत्यादि में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारत को सक्षम बनाने हेतु चालक बल रहा है। नैसर्गिक के मुताबिक, यह सालाना आधार पर 126 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात सहित 168 अरब अमरीकी डॉलर का अनुमानित राजस्व पैदा कर रहा है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान दे रहा है। यह उद्योग संगठित क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक बड़ा नियोक्ता भी है, जो लगभग 14 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि उद्योग 2025 तक 350 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान कर सकता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के ~ 10 प्रतिशत के बराबर है।

I.2. वर्ष 2015 में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय आईटी उद्योग प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता और लागत पर विश्व स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। यह कार्यक्रम भारत को प्रौद्योगिकी के आधार पर एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में परिवर्तित कर रहा है, जो समावेशी, किफायती और टिकाऊ है। इसने डिजिटल समावेशन की सामान्य परम्परा के साथ डिजिटल एक्सेस,

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन के अंतराल को दूर करना सुनिश्चित किया है। नतीजतन, भारत का डिजिटल फुटप्रिंट वर्ष 2025 तक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी बनने की संभावना के साथ दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। डिजिटल परिवर्तन का भारत का आंदोलन वैश्विक समानता के साथ आगे बढ़ रहा है।

- I.3. भारत का आईटी उद्योग मुख्य रूप से एक सेवा पर आधारित उद्योग है। भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए भारतीय आईटी उद्योग की क्षमता और देश में नवीन और तकनीकी क्षमताओं के निर्माण के लिए जबरदस्त गुंजाइश है। नैसकॉम की सामरिक समीक्षा 2017 के अनुसार वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग का मूल्य अनुमानतः 413 अरब अमेरिकी डॉलर है। हालांकि, भारतीय आईटी-आईटीईएस राजस्व में सॉफ्टवेयर उत्पादों का योगदान सिर्फ 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात शामिल है। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर उत्पादों का आयात लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, इस प्रकार भारत वर्तमान में सॉफ्टवेयर उत्पादों का निवल आयातक है। इसलिए, मुख्य रूप से सेवा उन्मुख भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग को एक तकनीकी उन्मुख उत्पाद और सेवा उद्योग में बदलने के लिए एक अनुकूल सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना समझदारी है।
- I.4. सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं में नवाचार, बौद्धिक संपदा (आईपी) निर्माण और बड़ी मूल्य वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, जिनमें इस क्षेत्र में राजस्व और निर्यात को काफी हद तक बढ़ावा देने की क्षमता है, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में वास्तविक रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत उपलब्ध लाभदायक अवसरों का लाभ उठाना आदि शामिल हैं। इस प्रकार, समावेशी और टिकाऊ विकास में वृद्धि हुई है।
- I.5. सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के विकास के परिणामस्वरूप भारतीय आईटी / आईटीईएस क्षेत्र के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए और इसलिए समग्र अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बाहुताएं हो सकती हैं, इसके लिए प्लेटफॉर्म के विकास को सुविधाजनक बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान उत्पन्न किए जाएं, जो संबंधित क्षेत्र की अपरिपक्व विकास क्षमता को परिपक्व बनाएगा। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अधिकतम लाभ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉक चेन इत्यादि जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी के उन्नयन के साथ गति बनाए रखने के लिए उच्च स्तर के नवाचार की आवश्यकता होती है। मूल्यवर्धन जो इस प्रकार से घटित होगा, उसमें अत्यधिक क्षमता के अहसास से प्रत्येक क्षेत्र की विकास दर को बढ़ावा मिलेगा, जिसका मुख्य रूप से पूरी तरह से अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- I.6. भारत में सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग की इष्टतम तरीके से क्षमता का एहसास करने के लिए एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जहां उद्योग जगत, शिक्षा जगत और सरकार देश के आईटी / आईटीईएस क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए समानता और सहक्रिया के साथ काम करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में " राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति" (एनपीएसपी) पहला महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का लक्ष्य आईसीटी के आधार पर इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी शुरुआत और विशेष कौशल सेट को बढ़ावा देने, नवाचार, बेहतर व्यावसायीकरण, टिकाऊ बौद्धिक संपदा (आईपी) द्वारा संचालित वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद केंद्र के रूप में भारत को विकसित करना है।

## II. शर्तें और परिभाषाएं

इस नीति के प्रयोजन से और इसके कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित शर्तों और परिभाषाओं पर विचार किया जाएगा:

- क. **भारतीय कंपनी:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा 26 के अनुसार "भारतीय कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी अभिप्रेत है, बशर्ते कि कंपनी, निगम, संस्था, एसोसिएशन या निकाय, जैसा भी मामला हो, का पंजीकृत कार्यालय या मुख्य कार्यालय भारत में हो।
- ख. **भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियां (आईएसपीसी):** आईएसपीसी को एक ऐसी भारतीय कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 51% या अधिक शेयरधारिता भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के पास है और सॉफ्टवेयर उत्पादों के विकास, व्यावसायीकरण, लाइसेंसिंग और बिक्री/सेवा में लगी हुई है और सॉफ्टवेयर उत्पाद (उत्पादों) के बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार उसके पास हैं।
- ग. **सॉफ्टवेयर उत्पाद:** सॉफ्टवेयर उत्पाद एक कंप्यूटर या नेटवर्क द्वारा प्रयुक्त या उत्पादित एक प्रोग्राम है जिसे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संग्रहीत या प्रसारित किया जा सकता है और किसी न किसी प्रकार की उपयोगिता प्रस्तावित करता है। इसके अलावा, इस तरह के उत्पाद को भारत में अनुमेय बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है और लाइसेंस के माध्यम से उपयोग के लिए इसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है।
- घ. **एमएसएमई:** एमएसएमई की परिभाषा वही होगी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 या प्रशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार की जाएगी।
- ङ. **स्टार्टअप:** स्टार्टअप की परिभाषा वही होगी, जो 11 अप्रैल, 2018 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा अधिसूचित राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 364 (ई) के अनुसार होगी या प्रशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित की जाएगी।

## III. विजन

एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में भारत को विकसित करना और बौद्धिक पूंजी संचालित सॉफ्टवेयर उत्पादों की अवधारणा, डिजाइन, विकास और उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थिति में आना, इस प्रकार, देश के आईटी उद्योग के पूरे स्पेक्ट्रम के विकास में तेजी लाना है।

## IV. मिशन

- (i) बौद्धिक संपदा (आईपी) द्वारा संचालित एक टिकाऊ भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देना, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार के हिस्से में दस गुना वृद्धि हो सके।

- (ii) सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना, जिसमें से टीयर-2 शहरों और टीयर-3 शहरों में ऐसी 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शामिल हैं और 2025 तक 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना।
- (iii) 3.2.3. सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए प्रतिभा पूल बनाना (i) 1,000,000 आईटी पेशेवरों का कौशल उन्नयन (अप-स्किलिंग), (ii) स्कूल और कॉलेज के 100,000 छात्रों को प्रेरित करना और (iii) 10,000 पेशेवरों को विशेषज्ञ बनाना जो नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं।
- (iv) एकीकृत आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, ऊष्मायन, आर एंड डी/टेस्ट बेड और सलाह देने वाले समर्थन वाले 20 क्षेत्रीय और रणनीतिक रूप से अवस्थित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करके क्लस्टर-आधारित नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- (v) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने और निगरानी करने के प्रयोजन से सरकार, अकादमिक जगत और उद्योग जगत के साथ भागीदारी से राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी।

## V. रणनीतियाँ

### 1. सॉफ्टवेयर उत्पाद व्यापार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना

- (i) उद्योग स्वामित्व के माध्यम से एक भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद प्राधिकरण (रजिस्ट्री) बनाई जाएगी। यह भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के एक आम पूल के रूप में कार्य करेगा जिससे कि एक विश्वसनीय व्यापार वातावरण प्रदान किया जा सके।
- (ii) पूँजीगत बाजार में सॉफ्टवेयर कंपनियों की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा।
- (iii) (i) आयात और निर्यात और (ii) सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्यमों को खोलने और बंद करने के संबंध में कानूनी और नियामक मुद्दों की तेजी से ट्रेकिंग में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग की सुविधा के लिए एक एकल विंडो प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा।
- (iv) भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली एक मॉडल एचएस कोड के माध्यम से विकसित की जाएगी। मॉडल एचएस कोड को सॉफ्टवेयर उत्पादों के प्रकार, सेवाओं और हार्डवेयर विनिर्माण सहित अन्य आर्थिक क्षेत्रों के साथ इसके इंटर-लिकेज के आधार पर आगे उप वर्गीकृत किया जाएगा। इस तरह के मॉडल वर्गीकरण से ऐसे उत्पादों के निर्यात पर नज़र रखने और सुगम बनाने में आसानी होगी। यह विशिष्ट क्षेत्रीय सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने में भी मदद करेगा।
- (v) भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों को स्वदेशी सॉफ्टवेयर उत्पादों के अनुसंधान और विकास में किए गए निवेश (उपार्जित आधार पर) पर देय कर, यदि कोई हो, को सेट ऑफ करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

### 2. रोजगार के लिए उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना

- (i) अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयोजन से कम से कम 10,000 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के पोषण के लिए ऊष्मायन का एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिससे 1 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

रोजगार अवसर पैदा होंगे। इनमें से 1000 स्टार्टअप को टीयर-2 शहरों और टीयर-3 शहरों में स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत (i) तकनीकी और बुनियादी ढांचा सहायता (ii) नेतृत्व सहायता, (iii) बीज निधि, (iv) आर एंड डी और परीक्षण सुविधाएं (v) विपणन और ब्रांडिंग समर्थन प्रदान करेगा।

- (ii) निधियों की निधि के रूप में 1000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ के एक समर्पित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (एसपीडीएफ) बनाई जाएगी। एसपीडीएफ बाजार के लिए तैयार सॉफ्टवेयर उत्पादों की अप स्केलिंग को बढ़ावा देने के लिए उद्यम फंड में भाग लेगा। यह निधि प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप उद्यमों की पूंजी आवश्यकताओं और बैंकों जैसे पारंपरिक संस्थागत उधारदाताओं से उपलब्ध वित्तपोषण के बीच के अंतर को दूर करेगी। यह योजना 5000 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस बनाएगी, जिसका अंतिम लक्ष्य कम से कम 100 भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों को शामिल करना होगा, जिनका मूल्य 500 करोड़ रुपये होगा या जो 200 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगी। सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार एसपीडीएफ का वित्तीय प्रबंधन किसी पेशेवर वित्तीय संस्थान/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाएगा। ऐसी गतिविधि के प्रभाव से अन्य सहायता सेवाएं और आगे रोजगार पैदा होंगे।
- (iii) उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में सॉफ्टवेयर उत्पादों पर अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए 500 करोड़ रुपये के बजटीय व्यय के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत भागीदारी करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग-शिक्षा जगत के क्षेत्र में अनुसंधान में मौजूदा अंतराल को दूर करना और अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आदर्श, उच्च गुणवत्तायुक्त, सस्ते सॉफ्टवेयर उत्पादों के विकास को सुकर बनाना है। आईपी विकास की ओर जाने वाले अकादमिक/शोध संस्थानों के साथ ऐसे सहयोगी शोध के लिए भारतीय एमएसएमई और स्टार्ट-अप को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के शोध परिणामों को भाग लेने वाले एमएसएमई के व्यवसायों में अवशोषित किया जाए, ऐसे आवेदकों से इसी प्रकार का फंड सरकारी अनुदान के लिए पूर्व-आवश्यकता होगी। व्यावसायिक अनुवाद के फलस्वरूप नवाचार और अनुसंधान का पेशेवर तरीके से प्रबंधन करने के लिए स्थापित क्षमता वाले एक विशेषज्ञ संगठन की पहचान की जाएगी, जो फंड को कार्यान्वित करेगा।
- (iv) मंत्रालय, राज्य सरकारों और उद्योग निकायों/थिंक टैंक के साथ मिलकर सामाजिक चुनौतियों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, विशेष जरूरतों वाले व्यक्ति (दिव्यंगजन) आदि को हल करने के उद्देश्य से 20 समर्पित चुनौती अनुदानों को संगठित करने के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सामाजिक चुनौतियों के लिए सॉफ्टवेयर उत्पाद समाधान की पहचान के लिए रिसर्च फंड इस तरह के चुनौती अनुदानों / हैकथॉन का भी समर्थन करेगा।
- (v) ऑटोमोबाइल, कपड़ा, वित्तीय सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, ऊर्जा आदि जैसे मौजूदा उद्योग बाहुल्य क्षेत्रों के आसपास 20 डोमेन विशिष्ट भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद क्लस्टर बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इन क्लस्टरों में कम से कम 500 प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के लिए एकीकृत आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, ऊष्मायन, आर एंड डी / टेस्ट बेड और नेतृत्व सुविधाएं उपलब्ध होगी। कम 500 प्रौद्योगिकी कंपनियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि ग्लोबल फुट प्रिंट का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

- (vi) उद्योग भागीदारी के साथ सॉफ्टवेयर उत्पादों के डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
- (vii) साइबर सुभेद्यता की पहचान करने और रोकने के लिए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पाद डिजाइनरों का समर्थन करने हेतु एक सामान्य अपग्रेड करने योग्य आधारभूत अवसंरचना बनाई जाएगी।

### 3. कौशल विकास और मानव संसाधन विकास

- (i) भविष्य की प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित जनशक्ति की बड़े पैमाने पर आवश्यकता को पूरा करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में 3 मिलियन आईटी पेशेवरों के अप-स्किलिंग/पुनः स्किलिंग के लिए एक भावी कार्यक्रम शुरू किया गया है। आईपी संचालित सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए आवश्यक दक्षताओं वाले 1 मिलियन आईटी पेशेवरों का प्रतिभा पूल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर उत्पादों से संबंधित मॉड्यूल पर एक विशेष जोर देने के तथ्य को इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। इसे (i) मौजूदा पाठ्यचर्या में संशोधन, (ii) अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, (iii) उद्योग के साथ परामर्श से राष्ट्रीय योग्यता परीक्षण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों, चिह्नित उद्योग निकायों और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के साथ साझेदारी से किया जाएगा।
- (ii) सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास के लिए युवा प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए स्कूल और कॉलेज के 100,000 छात्रों के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय "प्रतिभा त्वरक" कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- (iii) उत्पाद उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी और बौद्धिक पूंजी के विकास हेतु मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के लिए 10,000 प्रतिबद्ध सॉफ्टवेयर उत्पाद प्रणेताओं का एक प्रतिभा पूल बनाया जाएगा जो विशिष्ट कौशल सेट की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और सॉफ्टवेयर उत्पाद इनक्यूबेटर और क्लस्टर के लिए सलाहकार पूल के साथ उपयुक्त रूप से अंतःस्थापित होगा।

### 4. घरेलू बाजार तक पहुंच में सुधार करना और सीमा पार व्यापार का संवर्धन

- (i) भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की रजिस्ट्री को सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के साथ एकीकृत किया जाएगा और यह विपणन साह्यता के लिए भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
- (ii) भारतीय उत्पाद स्टार्ट-अप/एमएसएमई को स्मार्ट शहरों, स्वास्थ्य, कृषि, ई-लर्निंग, परिवहन, फिन-टेक और जैसे सामाजिक चुनौतियों जैसे डिजिटल डिवाइड, लिंग असमानता को दूर करने, कम सुविधा और विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे स्टार्टअप/एमएसएमई की पहचान के लिए हैकथॉन की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिन्हें सफल विकास पर उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।
- (iii) लगातार बढ़ते नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों पारिस्थितिक तंत्र में अंतर-संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लिए ओपन एपीआई के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा।

- (iv) सार्वजनिक खरीद (भारत में निर्मित को वरियता) आदेश, 2017 के अनुरूप सरकारी खरीद में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद के अधिमान्य समावेशन के लिए एक सक्षम ढांचा विकसित किया जाएगा।
- (v) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास कार्यक्रमों में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा :
  - क) भारत के विदेशी सहायता कार्यक्रमों में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों को एकीकृत करना।
  - ख) महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों आदि में अभिनव उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न बाजार विकास सहायता कार्यक्रमों के तहत अवसर और पहुंच प्रदान करना।
  - ग) वैश्विक बाजारों में भारतीय नवाचार की उपस्थिति को बढ़ाने हेतु सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास के लिए भारत और विदेश में विशिष्ट अवसरचना की स्थापना करना।
  - घ) उद्योग को प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और उनके और अंग्रेजी सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के बीच तकनीकी सेतु बनाने के लिए उत्पाद विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और वित्तीय सहायता दी जाएगी।

## 5. कार्यान्वयन तंत्र

- (i) सरकार सरकार, शिक्षा और उद्योग के साथ भागीदारी से एक संयुक्त सचिव के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में एक "राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (एनएसपीएम)" की स्थापना करेगी।
- (ii) मिशन के व्यापक उद्देश्य निम्नानुसार होंगे: -
  - क) सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के विकास के लिए उचित रणनीति तैयार करना ताकि इसकी क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और भारत को वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद हब के रूप में स्थापित किया जा सके।
  - ख) आईसीटी के उपयोग के आधार पर डिजाइन, विकास, नवाचार, मूल्य वृद्धि, (विज्ञान से दूसरे शब्द लें) के लिए एक सक्षम पारिस्थितिक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।
  - ग) सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पूरी क्षमता का भरपूर उपयोग करने के लिए की जाने वाली विशिष्ट पहलों की सिफारिश करना।
  - घ) इस नीति के तहत 3.5 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करने और 2025 तक सॉफ्टवेयर उत्पादों के राजस्व को दस गुना बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों की निगरानी करना और एकत्रित करना।
  - ङ.) इस नीति के तहत परिकल्पित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर उत्पादों के प्रचार में विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य निकायों की सुविधा प्रदान करना।
  - च) राज्यों को कार्यक्रमों में भाग लेने और इस नीति के अनुरूप भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - छ) एसपीडीएफ, रिसर्च एंड इनोवेशन फंड की निगरानी करना।

- ज) संदर्भ की आवश्यकतानुसार कोई अन्य उपाय करना।
- (iii) नीति का कार्यान्वयन एनएसपीएम की सिफारिश के अनुसार उपयुक्त कार्यक्रम और योजनाएं शुरू करके एमईआईटीवाई द्वारा किया जाएगा, जिसमें एमईआईटीवाई के संगठन जैसे प्रगत संगणन विकास केंद्र (सीडीएसी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), उद्योग और उद्योग निकाय और उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2019

#### Subject: National Policy on Software Products (2019)

##### No 15(5)/2015-ICD (vol I).—I. Preamble

- I.1. The Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT-ITES) industry of the country is a critical pillar in India's economic growth. The industry has potential to be a driving force for enabling India to develop capabilities for harnessing new technologies cutting across all the sectors, namely, agriculture, health, education, manufacturing etc, thereby creating significant employment and entrepreneurial opportunities. According to NASSCOM the sector at present is generating an estimated revenue of around USD 168 billion, including export of USD 126 billion on an annual basis, which is around 8% contribution to India's GDP. The industry is also one of the largest organised sector employers, generating nearly 14 million direct and indirect jobs. It is further estimated that the industry can contribute up to 350 billion USD accounting to ~10 percent of India's GDP by 2025.
- I.2. The Digital India Programme, launched by the Government in 2015, has ensured that the Indian IT industry delivers world class services at competitive quality and costs. The programme is leading to a transformation of India into a knowledge-based economy and digitally empowered society based on technology that is inclusive, affordable and sustainable. This has ensured digital access, digital infrastructure, digital empowerment and bridging of digital divide with the common thread of digital inclusion. As a result, India's Digital footprint is one of the fastest growing in the world with the potential to become a Trillion Dollar Digital Economy by 2025. India's movement of digital transformation is finding global resonance.
- I.3. The India's IT industry is predominantly a service led industry. There is tremendous scope for Indian Software Products to build upon the strength of Indian IT industry, and the innovative & technological capabilities in the country. As per NASSCOM Strategic Review 2017, the Global Software Product Industry is estimated to be USD 413 billion. However, the contribution of Software Products in Indian IT-ITES revenue is just USD 7.1 billion out of which 2.3 billion USD are exports. On the other hand import of Software Products is estimated to be nearly 10 billion USD, so as such India is a net importer of software products at present. Therefore, it is prudent to develop a conducive Software product ecosystem to transform a predominantly service oriented Indian IT/ITeS industry into a technology oriented products industry.



- I.4. The Software product ecosystem is characterised by innovations, Intellectual Property(IP) creation and large value addition increase in productivity, which has the potential to significantly boost revenues and exports in the sector, create substantive employment and entrepreneurial opportunities in emerging technologies and leverage opportunities available under the Digital India Programme, thus, leading to a boost in inclusive and sustainable growth.
- I.5. The development of the software product industry will result in positive externalities for the entire spectrum of the Indian IT/ITeS sector, and hence for the overall economy, by facilitating development of platforms that ensure that technology-based solutions are generated for sector-specific areas, that will tap the untapped growth potential of the sector concerned. Further, leveraging new and emerging technologies like Artificial Intelligence, Internet of Things, Block Chain etc. to the maximum advantage across sectors of the economy requires higher levels of innovation, keeping pace with the advancement of technology globally. The value addition that will so occur will boost the growth rate of each of the sectors by realisation of the immense potential therein, that is largely yet to be exploited to the fullest.
- I.6. To realise the potential of the software product industry in India in an optimal manner, there is a need for a framework where industry, academia and government work in synergy to bring about a paradigm shift in the IT/ITES sector of the country. The “National Policy on Software Product” (NPSP) is the first significant step towards achieving this goal. The policy aims to develop India as the global software product hub, driven by innovation, improved commercialisation, sustainable Intellectual property (IP), promoting technology start-ups and specialised skill sets, for development of the sector, based on ICT.

## II. Terms & Definitions

For the purpose of this policy and its implementation following terms and definitions will be considered:

- a. **Indian Company:** As per sub-section 26 of section 2 of the Income Tax Act, 1961, "Indian company" means a company formed and registered under the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013, provided that the registered office or, as the case may be, principal office of the company, corporation, institution, association or body in all cases is in India.
- b. **Indian Software Product Companies (ISPC):** An ISPC is defined as an Indian company in which 51% or more share holding is with Indian citizen or person of Indian origin and is engaged in the development, commercialisation, licensing and sale /service of Software products and has IP rights over the Software product(s).
- c. **Software Product:** Software product is a programme used or produced by a computer or network which can be stored or transmitted through an electronic medium and offers some form of utility. In addition, such a product can be protected in India through permissible Intellectual Property Right laws and can be commercialized for use through licensing.
- d. **MSME:** The definition of MSME will be as per Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 or amended from time to time by administrative department.
- e. **Startup:** The definition of startup will be as per Gazette Notification No. G.S.R. 364(E) dated April 11, 2018 notified by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) or amended from time to time by administrative department.

### **III. Vision**

To develop India as a Software Product Nation and a global leader in conception, design, development and production of intellectual capital driven Software Products, thus, accelerating growth of entire spectrum of IT Industry of the country.

### **IV. Missions**

- (i) To promote the creation of a sustainable Indian software product industry, driven by intellectual property (IP), leading to a ten-fold increase in share of the Global Software product market by 2025.
- (ii) To nurture 10,000 technology startups in software product industry, including 1000 such technology startups in Tier-II and Tier-III towns & cities and generating direct and in-direct employment for 3.5 million people by 2025.
- (iii) To create a talent pool for software product industry through (i) up-skilling of 1,000,000 IT professionals, (ii) motivating 100,000 school and college students and (iii) specialise 10,000 professionals that can provide leadership.
- (iv) To build a cluster-based innovation driven ecosystem by developing 20 sectoral and strategically located software product development clusters having integrated ICT infrastructure, marketing, incubation, R&D/test beds and mentoring support.
- (v) In order to evolve and monitor schemes & programmes for the implementation of this policy, National Software Products Mission will be set up with participation from Government, Academia and Industry.

### **V. Strategies**

#### **1. Promoting Software Products Business Ecosystem**

- i. An Indian Software product registry will be created through industry ownership. This will act as a common pool of Indian Software Products thereby providing a trusted trade environment.
- ii. A conducive environment will be created in order to facilitate active participation of software companies in Capital Market.
- iii. A Single Window platform will be established for facilitation of Indian software product industry in fast-tracking legal and regulatory issues regarding (i) import and export and (ii) opening and closure of software product enterprises.
- iv. A classification system for Indian software products will be evolved through a model HS code. The model HS code will be further sub categorized based on the type of software products, its inter-linkages with other economic sectors, including services and hardware manufacturing. Such model classification will facilitate tracking and easing of export of such products. This will also help in evolving statistical data for further promotion of specific sectoral software products.
- v. The Indian Software Product Companies will be allowed to set off tax payable, if any, on the investments made (on an accrued basis) in R&D of indigenous software products.

## 2. Promoting Entrepreneurship & Innovation for Employment

- i. In order to create a conducive ecosystem, a programme of incubation will be initiated to nurture at least 10,000 software product startups, thereby generating direct and indirect employment for 1 million persons. 1000 of these startups shall be targeted to be set up in Tier-II and Tier-III town & cities. The programme will provide (i) Technical & Infrastructure assistance, (ii) Mentoring Support, (iii) Seed Fund, (iv) R&D & Testing facilities (v) Marketing and Branding support.
- ii. A dedicated Software Product Development Fund (SPDF) with a corpus of Rs. 1000 Crore will be created in the form of Fund of Funds. SPDF will participate in venture fund to provide risk capital so as to promote scaling up of market ready Software Products. The fund will fill the gap between the capital requirements of technology and knowledge based software product startup enterprises and funding available from traditional institutional lenders such as banks. This scheme will create a corpus of Rs. 5000 Crore with an end target to have at latest 100 Indian software product companies having valuation of Rs. 500 Crore or employing 200 persons. The SPDF will be financially managed by a professional Financial Institution/ Asset Management Company as per SEBI guidelines. Spin off effect of such activity would create other support services and further employment.
- iii. A Programme to support Research and Innovation on Software Products in Institutes of Higher Learning and Research will be initiated with a budgetary outlay of Rs. 500 Crore with participation from Government, Academia and Industry. The objective of the programme is to bridge the existing gaps in the Industry-Academia research and facilitate development of novel, high quality affordable software products through research and innovation. Financial support in form of a Grant-in-aid will be provided to Indian MSMEs and start-ups for undertaking such collaborative research with academic/ research institutes leading to IP development. To ensure that such research outcomes are absorbed in participating MSMEs businesses a matching fund from such applicants will be a pre-requisite for government grant. An expert organisation having established capabilities to professionally manage innovation and research leading to commercial translation will be identified to operationalise the fund.
- iv. A programme for organising 20 dedicated challenge grants will also be initiated with an aim to solve societal challenges, such as in Education, Healthcare, Sanitation, Agriculture, persons with special needs (Divyangjan) etc in collaboration with line Ministries, state governments and Industry Bodies/ Think Tanks. The Research fund will also support such challenge grants/ hackathons for identifying software product solutions for societal challenges.
- v. A Programme to create 20 domain specific Indian software product clusters around existing industry concentrations, such as in automobile, textile, financial services, electronic manufacturing, energy etc will be initiated. These clusters will have integrated ICT infrastructure, marketing, incubation, R&D/test beds and mentoring facilities. Technical and financial support will be extended up to 500 technology companies so as to achieve global foot print.
- vi. A Centre of Excellence will be set up to promote design and development of software products with industry participation.

- vii. A common upgradable infrastructure will be created to support startups and software product designers to identify and plug cyber vulnerability.

### **3. Skilling and Human Resource Development**

- i. For catering to large scale requirement of trained manpower in futuristic technologies, a Future Skills programme has been initiated for up-skilling/re-skilling of 3 million IT Professionals in emerging technologies. For creating a talent pool of 1 million IT professionals with competencies required for IP driven software products, a special emphasis on modules related to software products will be added into the programme. This will be implemented through (i) modification in existing course curriculum, (ii) short term training programme, (iii) national competency tests in consultation with the industry. The programme will be implemented in partnership with educational institutes, both public and private, identified industry bodies and the National Skill Development Mission.
- ii. A national “Talent Accelerator” programme targeting, 100,000 school and college students, will be initiated for motivating young talent for software product development.
- iii. A talent pool of 10,000 committed software product leaders will be created that can meet the distinct skill set requirement for the sector to move up the value chain for developing technology and intellectual capital for product industry and will be suitably interlinked with the mentor pool for software products incubators and clusters.

### **4. Improving Access to Domestic Market and Cross Border Trade Promotion**

- i. The registry of Indian software products will be integrated with Government e-market (GeM) and will also provide necessary handholding for marketing support.
- ii. Indian Product Startups / MSMEs will be encouraged to develop solutions for Smart Cities, healthcare, agriculture, e-learning, transport, fin-tech and addressing social challenges, such as, bridging digital divide, gender inequality, empowering the less privileged citizens and divyangjans. A series of hackathons will be organised to identify such startups / MSMEs, who will be suitably rewarded on successful development.
- iii. Implementation of open APIs will be proactively promoted both for public and private sector to foster incremental innovation and to encourage inter-operability in Indian software products ecosystem.
- iv. An enabling framework will be developed for preferential inclusion of Indian software product in Government procurement in line with the Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017.
- v. Special focus to Indian Software Products will be provided in international trade development programmes by:
  - a) Integrating Indian software products in India’s foreign aid programmes.
  - b) Providing opportunities and access under the various market development assistance programmes to showcase innovative products and solutions in important events, exhibitions, trade fairs etc.
  - c) Setting-up of specialized infrastructure in India and abroad for Software Product development so as to enhance presence of Indian Innovation in global markets.

- vi. Industry will be encouraged and incentivised to develop products to overcome language barriers across major Indian Languages and to create technological bridges between them and major international languages including English.

### 5. Implementation Mechanism

- i. The Government shall establish a “National Software Product Mission (NSPM)” to be housed in Ministry of Electronics and IT (MeitY) under a Joint Secretary, with participation from Government, Academia and Industry.
- ii. The broad objectives of the mission will be as follows:-
  - a) Design appropriate strategy for development of the software product industry to ensure optimum utilization of its potential and to establish India as a global Software Product Hub.
  - b) Recommend specific policy measures to ensure an enabling ecosystem for design, development, innovation, value addition, (take other words from Vision), based on use of ICT.
  - c) Recommend specific initiatives to be undertaken to tap the full potential of the domestic and the international markets for the Software product industry.
  - d) Monitor and collate various initiatives taken under this policy with an aim to create 3.5 million employment opportunities and boost software products revenue tenfold by 2025.
  - e) Facilitate various Government agencies and other bodies in promotion of Software Products, specific to the various programmes envisaged under this policy.
  - f) Encourage States to participate in programmes and promote Indian Software Products in line with this policy.
  - g) Monitor SPDF, Research & Innovation Fund.
  - h) Take any other measures as may be required in the context.
- iii. The Policy will be implemented by MeitY through initiation of appropriate programmes & schemes, as per recommendation of NSPM, in which MeitY’s organizations, such as, Software Technology Parks of India(STPI) shall play a lead role besides Centre for Development of Advanced Computing (CDAC), National Informatics Centre(NIC), Industry/ Industry bodies and Institutes of Higher Education & Research.

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.